दृष्टि The Vision

Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश

मई 2023

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश **3**

- लखनऊ की सौम्या मिश्रा के निर्देशन में कनाडा में 'मिलेट मेला' और 'स्वराज-स्वतंत्रता की गाथा' का आयोजन 3
- यूपी के पूर्व डीजीपी को बनाया गया यूपीसीए का निदेशक 3
- लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के लोगो, शुभंकर, मशाल, गान और जर्सी का शुभारंभ 4
- मेरठ के अमित कुमार शौर्य चक्र से सम्मानित 5
- प्रदेश के शत-प्रतिशत अन्नदाताओं को 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' का लाभ देने के लिये अभियान शुरू 5
- उत्तर प्रदेश की औद्योगिक निवेश और रोज़गार की नीति में होगा बदलाव 6
- नल कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर 6
- पेराई सत्र 2023-24 के लिये गन्ने के सट्टा एवं आपूर्ति नीति जारी 7
- उत्तर प्रदेश के गाँवों में इस साल बनेंगे 6458 खेल मैदान 8
- उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा 'फार्मास्युटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट' 8
- लखनऊ में बनेगी देश की पहली नाइट सफारी 8
- बरेली मंडल में बनेंगे 52 अन्नपूर्णा स्टोर 9
- नोएडा की तर्ज पर बसेगा ग्रेटर अलीगढ़ 9
- अलीगढ़ की अंजना गुप्ता बनीं उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में सर्वाधिक मत पाने वाली पार्षद 10
- आगरा फोर्ट से ताजमहल के बीच जल्द तैयार होगी मेट्रो रेलवे लाइन, दोनों स्टेशन के बीच टनल निर्माण शुरू 10
- महाराष्ट्र को पीछे छोड़ उत्तर प्रदेश बना भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य 11
- उत्तर प्रदेश सरकार और कोरिया गणराज्य के ग्योंगसांगबुक-डो प्रांत के बीच एमओयू 12
- श्रीरामचरितमानस अब विश्व का सबसे लंबा गीत : बनारस के जगदीश के नाम हुआ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 12
- कोयले को मीथेन में बदलने पर काम करेगा बीएचयू 13
- उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल संस्थानों में खुलेंगे इमरजेंसी मेडिसिन विभाग 13
- ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिये 'समर्थ अभियान' का शुभारंभ 14
- प्रधानमंत्री ने तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुरू होने की घोषणा की 14
- उत्तर प्रदेश में बनेंगे सात डेवलपमेंट रीजन 15
- फरमान मियां को मिला 'भारत गौरव रत्न' सम्मान 15
- बीएचयू बना देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय 16
- रैपिड रेल व मेट्रो के किनारे बसेंगे आधुनिक शहर 16

दृष्टि The Vision

नोट :

उत्तर प्रदेश

लखनऊ की सौम्या मिश्रा के निर्देशन में कनाडा में 'मिलेट मेला' और 'स्वराज-स्वतंत्रता की गाथा' का आयोजन

चर्चा में क्यों?

2 मई 2023 को उत्तर प्रदेश लखनऊ की सौम्या मिश्रा के निर्देशन में कनाडा के शहर टोरोंटो में पहली बार 'मिलेट मेला'और 'स्वराज -स्वतंत्रता की गाथा'का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्यक्रम में 2 साल से लेकर 65 साल तक के प्रतिभागियों ने भारत के 'स्वतंत्रता संग्राम एक गाथा'की प्रस्तुति की, इसमें 80 स्वतंत्रता सेनानियों का उल्लेख था।
- इस कार्यक्रम में भारत के 28 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों की 40 प्रकार के मिलेट से बने पारंपरिक व्यंजन शामिल थे।
- इस दौरान लखनऊ की सौम्या मिश्रा ने बताया कि इस नाटकीय-कथा के संपादन में लगभग तीन साल का समय लगा, इसमें 80 स्वतंत्रता सेनानियों का उल्लेख था और इसमें अधिकतर वे स्वतंत्रता संग्राम के हीरो शामिल थे, जिनके बारे में लोगों ने कभी भी नहीं सुना था।
- इसके बाद 'मिलेट रेसपी बुक'का डिजिटल अनावरण हुआ। इस किताब में होम कुकस की 34 व्यंजन विधियाँ शामिल हैं, जिन्हें चार श्रेणियों में बाँटा गया है।

यूपी के पूर्व डीजीपी को बनाया गया यूपीसीए का निदेशक

चर्चा में क्यों?

3 मई, 2023 को यूपी के पूर्व डॉयरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) देवेंद्र सिंह चौहान को उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) के डायरेक्टर पैनल में शामिल किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- लखनऊ के एक निजी होटल में यूपीसीए के अध्यक्ष निधिपति सिंघानिया की ऑनलाइन अध्यक्षता में हुई बैठक में यूपीसीए के 12 निदेशकों की सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया।
- विदित है कि यूपीसीए में पहली बार किसी प्रशासनिक अधिकारी को शामिल किया गया है।
- ज्ञातव्य है कि राजीव शुक्ला के इस्तीफे के बाद से यह पद खाली चल रहा था। अभी तक यूपीसीए के निदेशकों की सूची में 12 लोग कार्यरत थे लेकिन, अब देवेंद्र सिंह चौहान के जुड़ने से निदेशकों की संख्या 13 हो गई है।
- यूपीसीए के 12 निदेशकों में अध्यक्ष निधिपति सिंघानिया, अभिषेक सिंघानिया, युद्धवीर सिंह, रियासत अली, ताहिर हसन, अशोक चतुर्वेदी, प्रेम मनोहर गुप्ता, प्रदीप कुमार गुप्ता, श्याम बाबू, जावेद अख्तर, विजय गुप्ता और गजेंद्रनाथ तिवारी शामिल हैं।
- इसके अलावा आगामी सत्र में यूपीसीए के उत्थान को लेकर भी चर्चा की गई।
- लखनऊ में यूपीसीए की बैठक में देर रात तक यूपी में अंतर्राष्ट्रीय मैच कराने को लेकर मंथन चला। कई पदाधिकारियों ने यूपी में ज्यादा से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच कराने पर ज़ोर दिया। कई ने कानपुर के ग्रीनपार्क क्रिकेट स्टेडियम में भी मैच कराने का प्रस्ताव रखा है।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि मूल रूप से मैनपुरी के निवासी डॉ. देवेंद्र सिंह चौहान का जन्म 20 मार्च, 1963 को महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। उनके पिता शिवराम सिंह चौहान सतारा सैनिक स्कूल में शिक्षक थे। डॉ. चौहान एमबीबीएस हैं तथा 1988 बैच के आइपीएस हैं। वे 15 फरवरी 2020 से डीजी इंटेलिजेंस के पद पर तैनात थे। और मई 2022 में उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी बने।
- देवेंद्र सिंह चौहान 31 मार्च, 2023 को ये अपने पद से रिटायर हो गए।

लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के लोगो, शुभंकर, मशाल, गान और जर्सी का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

5 मई, 2023 को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश 2022 के आधिकारिक लोगो, शुभंकर, मशाल, गान और जर्सी को लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि यह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण है।
- खेल 25 मई से शुरू होकर 3 जून 2023 तक चलेंगे।
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चार मशाल रिले को भी हरी झंडी दिखाई जो अगले 20 दिनों के दौरान भारत के इस सबसे बड़े राज्य के पश्चिमी, पूर्वी, मध्य और बुंदेलखंड इलाके से होकर गुजरेगी।
- मुख्यमंत्री द्वारा यूनिवर्सिटी गेम्स के प्रतीक चिन्ह (लोगो) का शुभारंभ किया।
- केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रसिद्ध गायक पलाश सेन द्वारा रचित और गाए गए 'खेलो इंडिया- हर दिल में देश' शीर्षक खेलों के गान का विमोचन किया।
- इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी गेम्स की आधिकारिक जर्सी को लॉन्च किया, जिसे ललित उपाध्याय, सुधा सिंह और दिव्या काकरान जैसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ियों ने पहना और मंच पर आत्मविश्वास के साथ उसे प्रदर्शित किया।
- इस अवसर पर यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभंकर जीतू बारासिंघा, जो आकर्षक जीवंत राजकीय पशु और 'गर्व से गौरव' का प्रतीक है, का अनावरण किया गया।
- अंतिम अनावरण यूनिवर्सिटी गेम्स के मशाल का किया गया, जिसे उत्तर प्रदेश के दिग्गज खिलाड़ियों - ललित उपाध्याय, वंदना कटारिया, सुधा सिंह, विजय यादव, दानिश मुज्तबा द्वारा एक-एक करके मंच पर लाया गया।
- उल्लेखनीय है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 उत्तर प्रदेश का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह (लोगो) भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की समृद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रतीक चिन्ह राज्य की समृद्ध पारंपरिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, जो शिक्षा, बुनियादी ढांचा और खेल जैसे सभी पहलुओं में इसके विकास का आधार रहा है।
- शुभंकर जीतू, बारासिंघा का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक अद्भुत स्तनधारी है, जो एक शक्तिशाली शारीरिक बनावट और उल्लेखनीय गति वाला होता है। यह अपने स्वभाव में कौशल, नीति और धैर्य को प्रदर्शित करता है और अनुग्रह एवं सूक्ष्मता की प्रतिमूर्ति होता है, जो वास्तव में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, उत्तर प्रदेश की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। यह उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की शक्ति और प्रचुरता को प्रदर्शित करता है।
- खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक मशाल 'शक्ति' न केवल अपनी विरासत और भावना की प्रतीक है, बल्कि एक ऐसी जीवंत इकाई भी है जो ऊर्जा से भरी हुई है। प्रत्येक एथलीट को अपने अंतिम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिये प्रेरित करने हेतु गंगा नदी को 'शक्ति' पर उकेरा गया है और इस पर अंकित ऊपर की ओर इशारा करते हुए, भविष्य की ओर उन्मुख दिखने वाला तीर गौरवशाली अतीत और उत्तर प्रदेश के भविष्य का उत्सव मनाता है।

नोट :

- शक्ति के प्रकाश प्रदान करने वाले मूल में मोर पंख और कमल की पंखुड़ियां भी अंकित हैं, जो पहाड़ों को भी हिला सकने वाली अपनी शांत ऊर्जा को इंगित करती हैं और प्रेरणा और इच्छाशक्ति का एक शक्तिशाली स्रोत है।
- इस 12-दिवसीय केआईयूजी यूपी 2022 का आयोजन वाराणसी, नोएडा और गोरखपुर के अलावा राज्य की राजधानी लखनऊ में किया जाएगा।
- दिल्ली के डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में निशानेबाजी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। कबड्डी प्रतियोगिता 23 मई, 2023 को नोएडा में शुरू होगी, जबकि कुछ अन्य स्पर्धाएं 24 मई, 2023 को विभिन्न स्थानों पर भी शुरू होंगी।
- कौशल, नीति और धैर्य की विचारधारा से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में आधिकारिक तौर पर पर 25 मई से 03 जून, 2023 तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे, इनमें 200 भारतीय विश्वविद्यालयों के 4000 से अधिक एथलीट 21 खेल स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगे।

मेरठ के अमित कुमार शौर्य चक्र से सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

9 मई, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट अमित कुमार को जम्मू-कश्मीर में आतंकियो के खिलाफ हुए ऑपरेशन के दौरान अदम्य साहस दिखाने पर शौर्य चक्र से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- अमित कुमार को शौर्य चक्र श्रीनगर के बरजुल्ला इलाके में 12 अक्टूबर 2020 को हुए ऑपरेशन के लिये दिया गया है।
- विदित है कि 15 अगस्त, 2022 को उन्हें इस ऑपरेशन के साथ-साथ अन्य ऑपरेशन के लिये तीन पुलिस पदक से सम्मानित करने की घोषणा हुई थी।
- गौरतलब है कि अमित कुमार मेरठ के न्यू मीनाक्षीपुरम निवासी हैं। अमित का परिवार मूल रूप से बुलंदशहर ज़िले के गाँव निसुर्खा के निवासी हैं। इनके पिता जीत सिंह भी सेना से सेवानिवृत्त हैं।
- अमित ने आर्मी स्कूल मेरठ कैंट से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरठ कॉलेज से बीएससी और भौतिक विज्ञान में एमएससी की।
- वर्ष 2013 में अमित सीआरपीएफ में सीधे नियुक्त होकर अधिकारी बने। विभिन्न स्थानों पर तैनात रहने के बाद अप्रैल 2018 में उनकी नियुक्ति श्रीनगर स्थित वैली क्यूएटी के कमांडर के पद पर हुई। इस दौरान उन्होंने अनेक ऑपरेशन में हिस्सा लिया। वह 15 एनकाउंटर में टीम के साथ शामिल रहे, इनमें 30 आतंकवादी मारे गए और पाँच को जिंदा पकड़ा गया।
- इन साहसिक कार्यों की सराहना में सरकार अमित को अब तक 14 प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कर चुकी है। गत 29 अगस्त से उनकी तैनाती नई दिल्ली में वन सिग्नल सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर है।

प्रदेश के शत-प्रतिशत अन्नदाताओं को 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' का लाभ देने के लिये अभियान शुरू

चर्चा में क्यों ?

10 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के अब शत-प्रतिशत अन्नदाताओं को 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना'का लाभ देने के लिये राज्य सरकार बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें पुराने पंजीकृत किसानों के प्रकरणों और नये कृषकों को जोड़ा जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- पूरे प्रदेश में पीएम किसान लाभार्थी संतृप्तीकरण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग सहित कृषि विभाग के अधिकारी व कर्मचारी लगाए जाएंगे।

नोट :

- ग्राम पंचायत स्तर पर यह अभियान 22 मई से शुरू होगा जो 10 जून तक चलेगा।
- हालाँकि, इससे पहले ही 20 मई तक राज्य सरकार के अधिकारी घर-घर जाकर ऐसे कृषकों की सूची तैयार करने में जुटे हुए हैं, जो विभिन्न कारणों से इस योजना का लाभ लेने से अब तक वंचित हैं।
- ग्राम पंचायत स्तर पर अभियान से पहले घर-घर सर्वेक्षण एवं प्रचार-प्रसार का अभियान चलाया जाएगा। इसमें ग्राम प्रधान के नेतृत्व में ग्राम स्तरीय कर्मियों के साथ घर-घर सर्वेक्षण कर ऐसे कृषकों की सूची तैयार कर ली जाएगी, जो विभिन्न कारणों से इस लाभ से वंचित हैं।
- इस पूरे अभियान का नोडल कृषि विभाग होगा। ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले शिविरों में ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत सेक्रेटरी, लेखपाल, तकनीकी सहायक (कृषि), कॉमन सर्विस सेंटर, पोस्ट ऑफिस के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, जिससे कि ई-केवाईसी, बैंक खाते की आधार लिंकिंग एवं लैंड सीडिंग के काम को सफलतापूर्वक कराया जा सके।
- ज्ञातव्य है कि 'किसान सम्मान निधि योजना' के तहत 6000 रुपए प्रतिवर्ष की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र सीधे-सीधे इसकी मॉनीटरिंग कर रहे हैं।
- राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जिन्होंने अभी तक ओपेन सोर्स से आवेदन नहीं किया है। इसके अलावा ऐसे कृषक भी हैं जिन्होंने ओपेन सोर्स के तहत आवेदन तो किया है, मगर आवेदन अब तक स्वीकृत नहीं हुए हैं।
- साथ ही, जिन कृषकों का भूलेख अपडेट नहीं हुआ है, उन्हें भी आगामी किस्तें प्राप्त नहीं हो रही है। कई बार पंजीकृत कृषकों के भूलेख का सत्यापन होने के बावजूद उनके बैंक खाते का आधार से लिंक न होने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है।
- उल्लेखनीय है कि 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के तहत अब तक 13 किस्तों का वितरण पूरा कर लिया गया है। अब 14वीं किस्त के लिये ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश की औद्योगिक निवेश और रोज़गार की नीति में होगा बदलाव

चर्चा में क्यों?

11 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों की ज़रूरत को देखते हुए अपनी नई औद्योगिक निवेश और रोज़गार प्रोत्साहन नीति में बदलाव करने जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- नई औद्योगिक निवेश और रोज़गार प्रोत्साहन नीति में बदलाव के तहत ज़मीन खरीद पर स्टांप ड्यूटी में छूट की राशि की प्रतिपूर्ति होगी। साथ ही, कैपिटल सब्सिडी की सुविधा मेगा प्रोजेक्ट के लिये केस टू केस आधार पर तय होगी।
- उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 2022 में औद्योगिक निवेश और रोज़गार प्रोत्साहन नीति लॉन्च की थी।
- इस नीति का उद्देश्य दुनिया भर से निवेश जुटाते हुए उत्तर प्रदेश में रोज़गार पैदा करने वाला एक प्रगतिशील, अभिनव और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।

नल कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर

चर्चा में क्यों?

15 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीण परिवारों को सबसे अधिक नल कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश अब महाराष्ट्र को पछाड़ते हुए सबसे अधिक नल कनेक्शन देने वाला दूसरा राज्य बन गया है।

प्रमुख बिंदु

- ग्रामीण परिवारों को सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाले राज्यों में बढ़त बनाते हुए उत्तर प्रदेश ने 1,12,97,534 नल कनेक्शन दिये हैं। राज्य में प्रतिदिन 40 हज़ार से अधिक नल कनेक्शन दिये जा रहे हैं।
- विदित है कि राज्य ने 'नल से जल की आपूर्ति योजना' में यह नया मुकाम हासिल किया है।

नोट :

- गौरतलब है कि महाराष्ट्र जो अब तक दूसरे स्थान पर था, 1,11,22,327 नल कनेक्शन के साथ तीसरे स्थान पर पहुँच गया है।
- देश के ग्रामीण परिवारों को सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाले राज्यों में बढ़त बनाते हुए उत्तर प्रदेश की नजर टॉप पर विराजमान बिहार से आगे निकलने पर है।
- अन्य राज्यों के मुकाबले राज्य की ग्रामीण आबादी 2,65,93,949 के साथ सबसे अधिक है। इसके बाद भी सरकार की ओर से जल जीवन मिशन की 'हर घर नल का जल' योजना के कार्य को तेजी से पूरा कराया जा रहा है।

पेराई सत्र 2023-24 के लिये गन्ने के सट्टा एवं आपूर्ति नीति जारी

चर्चा में क्यों?

15 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा पेराई सत्र 2023-24 के लिये गन्ने की सट्टा एवं आपूर्ति नीति जारी कर दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- गन्ना आपूर्ति नीति के आधार पर ही प्रदेश के गन्ना कृषकों को गन्ने की पर्चियों के जारी करने सहित गन्ना आपूर्ति के लिये विस्तृत निर्देश चीनी मिलों को दिये हैं।
- संजय भूसरेड्डी ने बताया कि इस वर्ष की आपूर्ति नीति में प्रति कृषक गन्ना सट्टे की सीमा सीमांत कृषक (1 हेक्टेयर तक) के लिये अधिकतम 850 कुंतल से बढ़ाकर 900 कुंतल, लघु कृषक (2 हेक्टेयर तक) के लिये 1,700 कुंतल से बढ़ाकर 1,800 कुंतल तथा सामान्य कृषक (5 हेक्टेयर तक) के लिये 4,250 कुंतल से बढ़ाकर 4,500 कुंतल की गई है।
- उपज बढ़ोतरी की दशा में सट्टे की अधिकतम सीमा सीमांत, लघु एवं सामान्य कृषक के लिये क्रमश : 1,350 कुंतल से बढ़ाकर 1,400 कुंतल, 2,700 कुंतल से बढ़ाकर 2,800 कुंतल तथा 6,750 कुंतल से बढ़ाकर 7,000 कुंतल निर्धारित की गई है।
- राज्य में छोटे किसानों को बड़ी राहत देते हुए अब 60 कुंतल की जगह 72 कुंतल तक के सट्टा धारक गन्ना किसानों को छोटे कृषक की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। इससे इन सट्टा धारकों को 45 दिन के अंदर गन्ना आपूर्ति की सुविधा मिल सकेगी।
- इस वर्ष की सट्टा आपूर्ति में भूमि क्रय-विक्रय के प्रकरणों में बेसिक कोटा हस्तांतरण, ड्रिप विधि से सिंचाई करने वाले कृषकों को सट्टे में प्राथमिकता, सैनिकों, अर्द्धसैनिक बलों, भूतपूर्व सैनिकों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके विधिक उत्तराधिकारियों को गन्ना आपूर्ति में प्राथमिकता, उत्तम गन्ना कृषकों को उपज बढ़ोतरी हेतु नि:शुल्क प्रार्थना-पत्र देने की सुविधा एवं सट्टाधारक सदस्य कृषक की मृत्यु पेराई सत्र के दौरान होने पर सट्टा चालू रखे जाने संबंधी अन्य प्राविधान भी प्रमुख हैं।
- आपूर्तिकर्त्ता किसानों की अधिकतम गन्ना आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिये गत दो वर्ष, तीन वर्ष एवं पाँच वर्ष की औसत गन्ना आपूर्ति में से अधिकतम औसत गन्ना आपूर्ति को पेराई सत्र 2023-24 के लिये बेसिक कोटा माने जाने के निर्देश दिये गए हैं। इससे न केवल कृषकों की गन्ना आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी बल्कि चीनी मिलों को भी अधिक गन्ना प्राप्त हो सकेगा।
- इसके अलावा, जो कृषक पेराई सत्र 2022-23 में नये सदस्य बने हैं तथा एक वर्ष ही गन्ना आपूर्ति किये हैं, उनके एक वर्ष की गन्ना आपूर्ति को ही बेसिक कोटा माना जाएगा। अंतिम कैलेंडर स्मार्ट गन्ना किसान (ई.आर.पी.) की वेबसाइट caneup.in एवं मोबाईल ऐप E Ganna पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। कृषकों के लिये अतिरिक्त टर्मिनल लगाकर पूछ-ताछ केंद्र स्थापित किया जाएगा।
- राज्य में सैनिकों, अद्धसैनिक बलों, भूतपूर्व सैनिकों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके विधिक उत्तराधिकारियों को सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर गन्ना आपूर्ति में 20 प्रतिशत की प्राथमिकता दी जाएगी।
- इस वर्ष की आपूर्ति नीति में पेराई सत्र के मध्य यदि किसी गन्ना आपूर्ति कृषक का डबल बांड (दोहरा सट्टा) प्रकाश में आता है, तो ऐसे प्रकरण को केन इंप्लीमेंटेशन कमेटी की बैठक में रखकर संबंधित कृषक की गन्ना आपूर्ति/गन्ना मूल्य भुगतान पर रोक लगाए जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- इस व्यवस्था से गन्ना माफियाओं द्वारा अनियमित आपूर्ति अब संभव नहीं हो सकेगी।
- गन्ना समितियों के 30 सितंबर, 2023 तक बने सदस्य ही आगामी सत्र में ही गन्ना आपूर्ति की सुविधा पाएंगे। कृषकवार व ग्रामवार सर्वे सट्टा सूचियों का प्रदर्शन 20 जुलाई से 30 अगस्त, 2023 तक किया जाएगा।

नोट :

उत्तर प्रदेश के गाँवों में इस साल बनेंगे 6458 खेल मैदान

चर्चा में क्यों ?

17 मई, 2023 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिये राज्य सरकार द्वारा खेलकूद से संबंधित आधारभूत ढाँचे को मजबूत करने के क्रम में मनरेगा के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 6458 खेल मैदान बनाए जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- मनरेगा के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6458 खेल मैदान बनाने का लक्ष्य तय किया गया है।
- मनरेगा खेल मैदानों को मनरेगा पार्क के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर बुजुर्गों के घूमने-टहलने के साथ-साथ बच्चों के मनोरंजन हेतु झूले और किशोरों के लिये ओपेन जिम भी बनेंगे।
- विदित है कि प्रदेश में 2017-18 से 2022-23 तक 5 सालों में 23,576 खेल मैदान व मनरेगा पार्क बनाए गए हैं। इनके निर्माण पर 852 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।

उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा 'फार्मास्युटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट'

चर्चा में क्यों ?

17 मई, 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश में फार्मास्युटिकल सेक्टर के विकास की संभावनाओं पर चर्चा के दौरान फार्मा सेक्टर में शोध-अनुसंधान को एवं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में एक नवीन संस्थान 'फार्मास्युटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट' की स्थापना के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फार्मा मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों की संख्या में उत्तर प्रदेश देश का छठा सबसे बड़ा राज्य है, अब लक्ष्य देश में अग्रणी राज्य बनने का है। इसी प्रकार देश में फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में अभी राज्य का योगदान 2 प्रतिशत का है, जिसे 10-12 प्रतिशत तक पहुँचाने की आवश्यकता है।
- उन्होंने कहा कि प्रदेश में आईआईटीआर, सीडीआरआई, सीमैप और एनबीआरआई जैसे उच्चस्तरीय शोध संस्थान क्रियाशील हैं, जबकि एसजीपीजीआई, केजीएमयू जैसे अकादमिक संस्थान भी हैं। नियोजित प्रयासों से बीते कुछ वर्षों में लखनऊ बायोफार्मा हब के रूप में उभरकर आया है।
- फार्मास्युटिकल सेक्टर के लिये एकेटीयू व अन्य प्राविधिक शिक्षण संस्थान मानव संसाधन उपलब्ध कराने में सक्षम हैं। प्रदेश में फार्मा पार्क निर्माण की कार्यवाही चल रही है तथा मेडिकल डिवाइस पार्क का भी निर्माण किया जाएगा।
- उन्होंने कहा कि दवा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थानों, रिसर्च लैब और इंडस्ट्री, तीनों क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे में फार्मास्युटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना की जानी चाहिये। यह संस्थान मूलत: शोध और नवाचार पर केंद्रित होगा, साथ ही सेक्टर से संबंधित अन्य संस्थानों व इंडस्ट्री के बीच सेतु का काम करेगा।
- उन्होंने अधिकारियों को फार्मास्युटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट के स्वरूप के संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने और राजधानी लखनऊ में इसके लिये उपयुक्त भूमि चिह्नित करने के निर्देश दिये।

लखनऊ में बनेगी देश की पहली नाइट सफारी

चर्चा में क्यों ?

17 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कुकरैल के जंगलों में सिंगापुर की तर्ज़ पर देश की पहली नाइट सफारी और नए चिड़ियाघर की स्थापना के लिये केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) ने अनुमति-पत्र जारी कर दिया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि कैबिनेट ने पिछले साल अगस्त में कुकरैल में नाइट सफारी बनाने और राजधानी के चिड़ियाघर को भी वहीं स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी। तभी से वन विभाग इनकी स्थापना के लिये सभी तरह की एनओसी हासिल करने व औपचारिकताएँ पूरी करने में लगा हुआ था।
- उल्लेखनीय है कि कुकरैल के जंगल 2027.46 हेक्टेयर में फैले हुए हैं। यहाँ 350 एकड़ में देश की पहली नाइट सफारी तैयार होगी। 150 एकड़ में प्राणि उद्यान बनेगा। इसके लिये 1000 एकड़ ज़मीन ऐसी चिह्नित की गई है, जिससे वनक्षेत्र के मूल स्वरूप को कोई नुकसान नहीं होगा।
- दोनों परियोजनाओं पर करीब 1500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सीजेडए का अनुमति-पत्र मिलने के बाद अब वन विभाग परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिये किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सलाहकार की सेवाएँ लेगा।
- सलाहकार नियुक्त करने के लिये भी खुली निविदा से प्रस्ताव मांगे जाएंगे। ये कार्य इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड में किये जाएंगे। यानी, जो फर्म नाइट सफारी व चिड़ियाघर की स्थापना का ठेका लेगी, उसे तय मानकों पर सभी काम खुद करना होगा। इसके लिये ग्लोबल टेंडर आमंत्रित किये जाएंगे, क्योंकि कोई विशेषज्ञ एजेंसी अभी देश में इस काम के लिये मौजूद नहीं है।

बरेली मंडल में बनेंगे 52 अन्नपूर्णा स्टोर

चर्चा में क्यों ?

17 मई, 2023 को बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) के उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने बताया कि बरेली मंडल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 52 अन्नपूर्णा स्टोर बनाए जाएंगे, जहाँ रोजमर्रा की ज़रूरतों से संबंधित 40 प्रकार के सामान जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- खाद्य एवं रसद विभाग की प्रमुख सचिव वीना कुमारी, बरेली की मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) के उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने मंडल में बनाए जा रहे 52 अन्नपूर्णा स्टोर्स का मॉडल मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया।
- स्टोर में उचित दर की दुकान एवं जन सुविधा केंद्र होगा, जिसे अन्नपूर्णा स्टोर का नाम दिया गया गया है। गाँव के पंचायत भवनों में इसका निर्माण होगा।
- स्टोर 52 वर्गमीटर में होगा, जिसके सामने 4 फीट चौड़ा बरामदा/प्रतीक्षा शेड होगा। एक भाग में उचित दर की दुकान होगी। इसमें 200 क्विंटल खाद्यान्न रखने की व्यवस्था होगी। स्टोर के दूसरे भाग में जन सुविधा केंद्र एवं जनरल स्टोर का संचालन किया जाएगा। दुकान में ई-पास मशीन भी होगी।
- अन्नपूर्णा स्टोर के जनसुविधा केंद्र से आय, जाति, जन्म, निवास प्रमाण-पत्र, आधार, पेंशन व अन्य सेवाएँ मिलेंगी। विभिन्न प्रकार के बिल जमा किये जा सकेंगे। जनरल स्टोर में पाँच किलोग्राम वाले एलपीजी सिलिंडर, ई-स्टांप, अग्निशमन यंत्र मिलेंगे। माइक्रो एटीएम, बीसी सखी आदि की सेवाएँ भी मिलेंगी।

नोएडा की तर्ज पर बसेगा ग्रेटर अलीगढ़

चर्चा में क्यों ?

18 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में खैर रोड पर बसने वाला ग्रेटर अलीगढ़ एनसीआर की तर्ज पर तैयार किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- इसके लिये लखनऊ की कंसल्टेंसी फर्म ने इंटीग्रेटेड हाउसिंग टाउनशिप की थ्रीडी डिजाइन व फोटोग्राफ्स तैयार किये हैं। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) अलीगढ़-पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 300 हेक्टेयर में आवासीय योजना लेकर आया है।

नोट :

- विदित है कि बीते दिनों कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में टाउनशिप के लिये हरी झंडी मिल चुकी है। एडीए खैर रोड पर ग्राम मूसेपुर करीब जिरौली, जिरौली डोर, अटलपुर, अहमदाबाद, जतनपुर चिकावटी, रुस्तमपुर अखन व ल्हौसरा बिसावन में ज़मीन जुटाएगा।
- यह पूरा क्षेत्र केंद्र व प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर प्राथमिकता में शामिल है। इसी रोड पर डिफेंस कॉरीडोर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी आदि प्रोजेक्ट बन रहे हैं।
- वहीं, दिल्ली-एनसीआर के लिये अलीगढ़ को यह हाईवे जोड़ता है। जेवर एयरपोर्ट की कनेक्विटी के लिये भी यही मार्ग मुख्य है। इन तमाम वजहों के चलते एडीए की हाउसिंग टाउनशिप काफी महत्त्वपूर्ण रहेगी।
- टाउनशिप के लिये एडीए द्वारा लखनऊ की फर्म से डिजाइन आदि तैयार कराई गई है। एडीए के मुताबिक ग्रेटर अलीगढ़ सेक्टरों में विभाजित होगा। वहीं अलग-अलग श्रेणियों के फ्लैटों के टावर बनेंगे।
- अलीगढ़ विकास प्राधिकरण प्रदेश भर में लैंड पूलिंग योजना लागू करने वाला पहला ज़िला बन गया है। ट्रांसपोर्ट नगर योजना में नौ किसानों से कुल 10 हेक्टेयर भूमि इस योजना के तहत ली गई है। इससे पहले मथुरा और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी लैंड पूलिंग का प्रस्ताव तैयार किया था लेकिन इन विकास प्राधिकरण में संबंधित ज़मीनों का भू उपयोग परिवर्तन न होने के चलते मामला शासन में अटक गया।
- विदित है कि प्रदेश सरकार ने फरवरी 2019 में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में लैंड पूलिंग नीति लागू करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके तहत भू स्वामी को पाँच साल तक प्रति एकड़ पाँच हज़ार रुपए दिलाने के साथ ही 25 प्रतिशत क्षेत्रफल भी वापस करने का नियम तय हुआ।
- प्रत्येक भू-स्वामी को उसके द्वारा दी गई भूमि की विकसित भूमि का आनुपातिक हिस्सा लाटरी के माध्यम से नि:शुल्क आवंटित किया जाएगा। इसके आंतरिक व वाह्य विकास के लिये भू-स्वामियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

अलीगढ़ की अंजना गुप्ता बनीं उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में सर्वाधिक मत पाने वाली पार्षद

चर्चा में क्यों?

17 मई, 2023 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में अलीगढ़ की नवनिर्वाचित पार्षद अंजना गुप्ता ने 92.76% मत हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है।

प्रमुख बिंदु

- भाजपा की नवनिर्वाचित पार्षद अंजना गुप्ता ने वार्ड 43 से 92.76% मत हासिल कर यह उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में सबसे अधिक मत प्रतिशत हासिल करने का रिकॉर्ड अलीगढ़ में बना।
- नगर निकाय चुनाव में वार्ड 43 में कुल 10700 वोट में से 5078 वोट पड़े थे। इसमें अंजना गुप्ता को 4714 वोट मिले जबकि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को 201 मत मिले।

आगरा फोर्ट से ताजमहल के बीच जल्द तैयार होगी मेट्रो रेलवे लाइन, दोनों स्टेशन के बीच टनल निर्माण शुरू

चर्चा में क्यों?

21 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार आगरा फोर्ट से ताजमहल के बीच जल्द ही मेट्रो रेलवे लाइन तैयार होगी। 77 दिन के रिकॉर्ड टाइम में पहला ब्रेक थ्रू करने के बाद टीबीएम यमुना ने ताजमहल मेट्रो स्टेशन की दिशा में टनल का निर्माण शुरू कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि आगरा से पहले उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में मेट्रो शुरू हो चुकी है। लेकिन आगरा में मेट्रो का काम इसलिये भी खास है क्योंकि आगरा मेट्रो रेल परियोजना पहली ऐसी परियोजना है जहाँ टीबीएम लॉन्च के बाद महज 77 दिन के रिकॉर्ड टाइम में पहला ब्रेक थ्रू किया गया है।

- टीबीएम यमुना को फरवरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके बाद टीबीएम यमुना ने 77 दिन में पहला ब्रेक थ्रू करते हुए बिजली घर से आगरा फोर्ट तक की टनल का काम पूरा किया था।
- टीबीएम द्वारा भूमिगत मेट्रो लाइन के निर्माण को मुख्य तौर पर 3 चरणों में विभाजित किया गया है। इस प्रक्रिया में प्रथम चरण इनिशियल ड्राइव होता है, जिसमें टीबीएम लॉन्चिंग सॉफ्ट से चैनल की खुदाई का काम शुरू करती है।
- इस चरण में अस्थायी रिंग्स को मैनुअल तरीके से लगाया जाता है। इस दौरान मशीन में लगे थ्रस्ट जैक इन अस्थायी रिंग सेगमेंट्स की मदद से टीबीएम को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद टीबीएम मेन ड्राइव में पहुँचती है। टीबीएम खुदाई के साथ ही स्थायी रिंग सेगमेंट्स लगाते हुए टनल का निर्माण करती है। इसके बाद टीबीएम मशीन दूसरे छोर पर ब्रेक थ्रू करते हुए बाहर आती है।

महाराष्ट्र को पीछे छोड़ उत्तर प्रदेश बना भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य

चर्चा में क्यों ?

21 मई, 2023 को उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिलों के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश एक बार फिर भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है। चीनी उत्पादन में इसने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि 2022 में महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बना था। वर्ष 2021-22 में महाराष्ट्र द्वारा 138 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया था जबकि उत्तर प्रदेश द्वारा उत्पादित कुल चीनी 105 लाख टन था।
- चालू सीजन 2022-2023 में उत्तर प्रदेश में कुल 29 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है, जबकि महाराष्ट्र में 105.30 लाख टन का उत्पादन हुआ। प्रदेश में कुल 2,348 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ, जबकि महाराष्ट्र में 1,413 लाख टन का उत्पादन हुआ।
- 2022-2023 सीजन में उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की कुल गन्ने की पेराई 1,084.57 लाख टन थी, जबकि महाराष्ट्र में यह 1,053 लाख टन थी।
- विदित है कि उत्तर प्रदेश में कुल 157 चीनी मिलें हैं, जिनमें 118 परिचालन में हैं जबकि महाराष्ट्र में 246 मिलों में 210 परिचालन में हैं।
- चालू सीजन में उत्तर प्रदेश में 53 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती हुई, जो देश में किसी भी राज्य से ज्यादा है। महाराष्ट्र में इसका आधा यानी 14.87 लाख हेक्टेयर में ही खेती हुई थी।
- मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि 2022-23 के दौरान किसानों को 28,494 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इसमें से 80 चीनी मिलें ऐसी हैं, जिनका पूरा भुगतान एक सप्ताह के भीतर किया गया है। पिछले छह वर्षों में चीनी मिलों को कुल 2.11 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार और कोरिया गणराज्य के ग्योंगसांगबुक-डो प्रांत के बीच एमओयू

चर्चा में क्यों?

22 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश और कोरिया गणराज्य के ग्योंगसांगबुक-डो प्रांत के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गए, जिसके तहत दोनों प्रांतों में प्रगति एवं विकास के लिये शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश सरकार की ओर से अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह तथा ग्योंगसांगबुक-डो प्रांत के महानिदेशक, ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल अफेयर, ली यंगसेओक द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए।
- मुख्यमंत्री ने इस सहभागिता के महत्त्व और दोनों क्षेत्रों के बीच विकास और सहयोग के नए द्वार खोलने पर बल देते हुए कहा कि हस्ताक्षरित एमओयू दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांगबुक-डो प्रांत तथा उत्तर प्रदेश के बीच द्विपक्षीय सहयोग में वृद्धि की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश और दक्षिण कोरिया के पुराने आत्मिक रिश्ते फिर से प्रगाढ़ हो रहे है। दोनों देशों के स्वतंत्रता दिवस की तिथियां एक हैं। दोनों देशों के रिश्ते शताब्दियों पुराने हैं।
- विदित है कि दो हज़ार साल पहले अयोध्या की राजकुमारी श्रीरत्ना ने जल मार्ग से दक्षिण कोरिया की यात्रा की थी। उन्होंने जिमगवांन के राजा सुरो से विवाह किया था, जिसके बाद उन्हें हियो हवांग ओक के नाम से जाना गया।
- जिमगवांन साम्राज्य का प्रतीक जुड़वाँ मछली है, जो अयोध्या सहित उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में कई ऐतिहासिक स्मारकों में पाई जाती है।
- ज्ञातव्य है कि 6 नवंबर, 2018 को दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला किम जुंग सूक के साथ मुख्यमंत्री ने अयोध्या में क्वीन हो मेमोरियल पार्क का शिलान्यास किया था। इसका निर्माण पूरा हो चुका है। अयोध्या और कोरिया का गिम्हे शहर सिस्टर सिटी है।
- दुनिया की नामी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सैमसंग और एलजी जैसे बड़े उद्योग का जन्म दक्षिण कोरिया के जीबी प्रॉविंस में माना जाता है। प्रदेश 250 मिलियन की जनसंख्या के साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता केंद्र है।

श्रीरामचरितमानस अब विश्व का सबसे लंबा गीत : बनारस के जगदीश के नाम हुआ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड

चर्चा में क्यों?

23 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार श्रीरामचरितमानस अब विश्व का सबसे लंबा गीत बन चुका है। उत्तर प्रदेश के बनारस के डॉ. जगदीश पिल्लई ने 138 घंटे 41 मिनट और 20 सेकेंड के श्रीरामचरितमानस गीत को अपनी आवाज़ दी है।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि इसके पहले यह रिकॉर्ड अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के नाम था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने के साथ ही अमेरिका के नाम दर्ज ये रिकॉर्ड अब भारत के नाम हो चुका है।
- डॉ. जगदीश पिल्लई उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा यानी पाँच बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डधारी बन गए हैं।
- राज्य के आयुष मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु ने डॉ. जगदीश पिल्लई को उनके घर जाकर गिनीज प्रमाणपत्र प्रदान किया।
- गौरतलब है कि डॉ. जगदीश पिल्लई ने हिन्दी भाषी न होने के बावजूद अवधी में इतने सुंदर एवं भावनात्मक तरीके से भजन व कीर्तन के साथ इतने लंबे गीत को खुद धुन देकर गाया और इसे गिनीज बुक में दर्ज कराया। उन्हें इस काम को पूरा करने में चार साल का समय लग गया।
- श्रीरामचरितमानस गीत दुनिया भर के 100 से अधिक ऑडियो चैनल पर प्रसारित हो चुका है। इसलिये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने श्रीरामचरितमानस को लांगेस्ट ऑफिशियली रिलीज्ड सॉंग यानि आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त दुनिया के सबसे लंबे गाने के रूप में दर्ज किया है।

नोट :

- ज्ञातव्य है कि अब तक का सबसे लंबा गीत 115 घंटे 45 मिनट का था जो एक दिसंबर 2021 को सेंट एल्बंस हर्टफोर्डशायर (यूके) में रहने वाले मार्क क्रिस्टोफर ली और द पॉकेट गॉड्स ने गाया था। उन्होंने एक ही तरह के वाद्य संगीत बजाकर इस रिकॉर्ड को हासिल किया था।
- डॉ. जगदीश पिल्लई ने बताया कि 2016 से ही दुनिया के सबसे लंबे गाने के रिकॉर्ड को तोड़ने की इच्छा थी। उनका कहना है कि जब भारत में रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ हैं तो यह रिकॉर्ड भी भारत के ही नाम होना चाहिये। अवधी भाषा में होने के कारण पहले बोलचाल और उच्चारण को समझने के लिये मित्र प्रदीप मिश्रा की मदद ली।
- इसके बाद रिकॉर्डिंग के लिये मित्र दीपक जायसवाल से संपर्क किया। दीपक जायसवाल को भी गिनीज पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया।
- उल्लेखनीय है कि डॉ. जगदीश पिल्लई ने बनारस का नाम पहली बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2012 में दर्ज कराया था। उन्होंने सबसे कम समय में एनीमेशन मूवी बनाकर 2012 में एक कैनेडियन का रिकॉर्ड तोड़ा था। कैनेडियन ने जो काम छह घंटे में किया था, डॉ. पिल्लई ने उसे साढ़े तीन घंटे में पूरा किया।
- दूसरा रिकॉर्ड 16,300 पोस्टकार्ड से लांगेस्ट लाइन ऑफ पोस्टकार्ड बनाया। तीसरी बार लार्जेस्ट पोस्टर अवेयरनेस कैंपेन और चौथी बार योगा जनजागरूकता अभियान के तहत सबसे लंबा लिफाफा बनाकर अपना नाम गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज कराया था।
- वैदिक विज्ञान में पीएचडी करने वाले डॉ. पिल्लई पाँच सौ से ज्यादा पुस्तकों के लेखक हैं।

कोयले को मीथेन में बदलने पर काम करेगा बीएचयू

चर्चा में क्यों?

23 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार कोयला मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के वैज्ञानिकों को ग्रीन एनर्जी पर अपनी तरह का देश का पहला महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट दिया है, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक कोयले को ज़मीन के अंदर इसकी मूल स्थिति में ही मीथेन में बदलने पर काम करेंगे।

प्रमुख बिंदु

- ऊर्जा संकट के मद्देनज़र ही मंत्रालय ने कोयले के बायोमिथेनाइजेशन पर यह महत्त्वपूर्ण परियोजना दी है। इसके अंतर्गत अध्ययन में देखा जाएगा कि कोयले को इन-सीटू (वह प्राकृतिक व मूल स्थिति, जिसमें ज़मीन के भीतर कोयला रहता है) स्थिति में 'मीथेन' में बदलने में जैविक विधि कितनी कारगर होती है।
- यह अध्ययन बीएचयू के भूविज्ञान विभाग के प्रो. प्रकाश कुमार सिंह और वनस्पति विज्ञान की प्रो. आशालता सिंह करेंगी।
- प्रो. प्रकाश सिंह तथा प्रो. आशालता सिंह की टीम डीएसटी के एक अन्य प्रोजेक्ट में यह अध्ययन कर रही है कि भारत के पूर्वोत्तर और कुछ अन्य स्थानों में पाए जाने वाले सल्फर-युक्त कोयले से बायो केमिकल तकनीक द्वारा कैसे सल्फर कम किया जा सके। इससे सल्फर से होने वाली पर्यावरणीय क्षति से बचा जा सकता है।
- इस अध्ययन से दो परिणाम निकलेंगे। पहला यह कि कोयले को जमीन में ही मीथेन में बदलकर ग्रीन एनर्जी प्राप्त की जा सकेगी। दूसरा, कोयला खनन रोकने से पर्यावरण को होने वाले दुष्परिणाम से भी बचाया जा सकेगा।
- हाल ही में कोल इंडिया के सीएमपीडीआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने बीएचयू का दौरा किया और परियोजना की बारीकियों को जाना।

उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल संस्थानों में खुलेंगे इमरजेंसी मेडिसिन विभाग

चर्चा में क्यों?

24 मई, 2023 को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने राज्य के सभी मेडिकल विश्वविद्यालय, कॉलेज और शैक्षिक संस्थानों में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग को अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में उन्होंने विभाग की स्थापना को मंज़ूरी प्रदान कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। मेडिकल विश्वविद्यालय और संस्थानों में इमरजेंसी सेवाएँ चल रही हैं। मरीजों को और बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिये ही एनएमसी ने इमरजेंसी मेडिसिन विभाग की स्थापना के निर्देश दिये।
- इमरजेंसी सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। केजीएमयू, लोहिया संस्थान समेत अन्य शैक्षिक संस्थानों में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग संचालित हैं। इमरजेंसी की दशा में सबसे पहले मरीज इसी विभाग में आएंगे। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर रोगियों के लक्षणों के आधार पर मर्ज की पहचान करेंगे, तत्पश्चात् इलाज की दिशा तय करेंगे।
- डिप्टी सीएम ने कहा कि सभी मेडिकल संस्थानों में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग बनने से गंभीर रोगियों को बड़े अस्पतालों तक दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। इससे बड़े अस्पतालों में मरीजों का दबाव कम होगा। गंभीर मरीजों को आसानी से इलाज मिल सकेगा तथा मेडिकल छात्र क्लीनिकल ज्ञान भी हासिल कर सकेंगे।

ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिये 'समर्थ अभियान' का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

25 मई, 2023 को केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 'अमृत महोत्सव' के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिये 'समर्थ अभियान' का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिये 'समर्थ अभियान' चला रहा है, जो 1 फरवरी, 2023 से शुरू हुआ और 15 अगस्त, 2023 तक आजादी के 'अमृत महोत्सव' के अंतर्गत जारी रहेगा।
- 'समर्थ अभियान' का बड़ा जोर विशेष रूप से महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने पर है।
- इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का जो एनपीए 2013 में 9.58 प्रतिशत था, वो अब घटकर 2 प्रतिशत से नीचे आ गया है।
- इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अकेले उत्तर प्रदेश में ही बीसी सखियों द्वारा 5 करोड़ 57 लाख लेन-देन करके जो डिजिटल परिवर्तन लाया गया है, उसके जरिये बीसी सखियों ने न सिर्फ इतनी बड़ी आबादी को डोरस्टेप बैंकिंग के साथ अंतिम मील तक सेवाएँ दी हैं, बल्कि उन्होंने अपने परिसर के भीतर छोटे आकार वाले लेन-देन करके बैंकों के संसाधनों को लागत से बचाने में मदद की है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गाँवों में बनाए जा रहे डिजिटल ग्राम सचिवालयों में प्रत्येक बैंक सखियों को सेवाएँ देने का प्रावधान भी होगा।
- इस कार्यक्रम में बीसी सखियों की 75 प्रेरणादायक कहानियों के सार-संग्रह का अनावरण किया गया और इसके साथ ही बीसी सखियों ने अपने जीवन में हुए कायापलट की जीवंत गवाहियों और सफलता की कहानियाँ इस कार्यक्रम में सुनाईं।
- इसके अलावा बीसी सखियों को बायोमेट्रिक पीओएस मशीन भी वितरित की गईं और नवनियुक्त बीसी सखियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए।
- इस कार्यक्रम में पूरे भारत से लगभग 1000 बीसी सखियों ने भाग लिया। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) और पूरे भारत के अन्य हितधारक वेबकास्ट के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस कार्यक्रम को सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम किया गया।

प्रधानमंत्री ने तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुरू होने की घोषणा की

चर्चा में क्यों?

25 मई, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (केआईयूजी) 2023 के शुरू होने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन 25 मई से 3 जून तक उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। इन खेलों का समापन समारोह तीन जून को वाराणसी में होगा।
- तीसरे केआईयूजी में देश के 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4750 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं, जो 21 खेल श्रेणियों में प्रतिस्पर्द्धा करेंगे।
- खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के इस संस्करण का शुभंकर 'जीतू', उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंघा को बनाया गया है।
- विदित है कि 23 मई, 2023 को ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक (एसवीएसपी) स्टेडियम में पुरुषों और महिलाओं के कबड्डी के ग्रुप लीग खेल से केआईयूजी की शुरुआत हो चुकी है।
- सात अन्य खेलों- बास्केटबॉल, फुटबॉल, रग्बी, टेनिस, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और मल्लखंब के प्रारंभिक दौर और समूह खेल भी 24 मई, 2023 को लखनऊ के तीन स्थानों पर शुरू हुए।
- राज्य के चार शहर लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और नोएडा विभिन्न खेलों की मेजबानी करेंगे, जबकि दिल्ली के डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज, शूटिंग स्पर्द्धा की मेजबानी करेगा।
- गोरखपुर के रामगढ़ ताल में होने वाली रोइंग स्पर्द्धा, इस केआईयूजी के साथ वाटर-स्पोर्ट्स की शुरुआत को भी सुनिश्चित करेगी।
- विदित हे कि प्रधानमंत्री ने देश में खेल की संस्कृति को और विकसित करने तथा देश के युवाओं को खेलों के लिये प्रोत्साहित करने पर बहुत ध्यान दिया है। सरकार द्वारा उदीयमान खिलाड़ियों को सहयोग देने के लिये विभिन्न योजनाएँ शुरू की गई हैं और देश में खेल के इकोसिस्टम को मजबूत करने के प्रयास किये गए हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन इसी दिशा में एक और शानदार कदम है।

उत्तर प्रदेश में बनेंगे सात डेवलपमेंट रीजन

चर्चा में क्यों ?

28 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार शहरी विकास के लिये गठित केंद्र सरकार की हाई लेबल कमेटी ने उत्तर प्रदेश में सात डेवलपमेंट रीजन बनाए जाने की सिफारिश राज्य सरकार को भेजी है।

प्रमुख बिंदु

- इसमें रीजनल प्लानिंग के तहत रिवर फ्रंट डेवलपमेंट व ग्लोबल गेटवे सिस्टम के विकास पर फोकस होगा। रिवर डेवलपमेंट से आवास एवं रोज़गार की समस्या हल की जाएगी।
- कमेटी के चेयरमैन केशव वर्मा ने एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ में स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) बनाने की सिफारिश भी की है। इसमें लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर व हरदोई ज़िलों को शामिल करने का प्रस्ताव है।
- इसके अतिरिक्त छह अन्य डेवलपमेंट रीजन मेरठ, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली एवं झाँसी में बनाने की सिफारिश की गई है। एससीआर का मुखिया मुख्य सचिव हो सकते हैं, लेकिन अन्य रीजन की ज़िम्मेदारी मंडलायुक्त को सौंपी जा सकती है।
- कमेटी के चेयरमैन ने कहा है कि प्रदेश भर में मेट्रो का संचालन संभव नहीं है। इसमें जितनी पूंजी का निवेश होता है, उतनी आय नहीं हो रही। ऐसे में राज्य सरकार को छोटे शहरों में सुगम आवागमन के लिये ट्रामा सिस्टम को विकसित करना चाहिए। इससे कम पूंजी से लोगों को सस्ता सफर हासिल हो सकेगा।
- रीजनल प्लानिंग से शहर से लेकर गाँव तक के विकास का रास्ता खुल जाएगा। इससे वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की लक्ष्य पूरा होने के साथ ही लोगों को आसानी से आवास व रोज़गार मिल सकेंगे।

फरमान मियां को मिला 'भारत गौरव रत्न' सम्मान

चर्चा में क्यों ?

26 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की ओर से उत्तर प्रदेश के बरेली के जमात रजा मुस्तफा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान हसन खां (फरमान मियां) को 'भारत गौरव रत्न' सम्मान दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार मानवता और सामाजिक कार्यों के लिये मिला है।

प्रमुख बिंदु

- फरमान मियां ने कैंसर पीड़ित मरीजों का आपरेशन, कूल्हों का आपरेशन, बाइपास सर्जरी के दर्जनों मरीजों को इलाज में मदद की है।
- इससे पहले उन्हें मिनिस्ट्री आफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ओर से टीबी मुक्त अभियान में सार्थक भूमिका निभाने के लिये पुरस्कार मिल चुका है।
- विदित है कि इससे पहले भी फरमान मियां को कई पुरस्कार मिल चुके हैं-
- मिनिस्ट्री आफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ओर टीबी मुक्त अभियान में सार्थक भूमिका निभाने के लिये पुरस्कार मिला।
- नेशनल कमीशन फार वूमेन, इंडिया की ओर से महिलाओं के अधिकारों को लेकर अच्छे कार्य करने पर पुरस्कार मिला।
- नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की ओर मानवाधिकारों के संरक्षण में अहम योगदान के लिये भी पुरस्कार मिल चुका है।
- कर्नाटक की भारत यूनिवर्सिटी ने फरमान हसन खाँ को डाक्टरेट मानद उपाधि से नवाज़ा है।

बीएचयू बना देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय

चर्चा में क्यों?

29 मई, 2023 को आईआईआरएफ (इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क) की तरफ से जारी रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) को देश में दूसरा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय घोषित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- शिक्षण संस्थानों में शिक्षण,अनुसंधान गुणवत्ता व उत्पादकता, प्लेसमेंट, उद्योग से जुड़ाव, प्रतिष्ठा व छवि समेत कई मापदंडों को आधार बनाकर आईआईआरएफ रैंकिंग देती है।
- देशभर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में बीएचयू को 1000 में 982.95 अंक दिये गए हैं। पहले स्थान पर आए जेएनयू को 983.12 अंक और तीसरे स्थान पर एएमयू को 982.88 अंक मिले हैं।
- अन्य विशिष्ट विश्वविद्यालयों में जामिया मिलिया इस्लामिया, हैदराबाद विश्वविद्यालय, डीयू और पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं।
- रैंक तालिका में बीएचयू को प्लेसमेंट और इंटरनेशनल आउटलुक के मामले में जेएनयू से ज्यादा अंक मिले हैं, जबकि शिक्षण, शोध, प्लेसमेंट व्यवस्था में यह मामूली अंतर से टॉप यूनिवर्सिटी से पीछे रहा है। पहले स्थान पर आए जेएनयू से बीएचयू को 0.17 अंक ही कम मिले हैं।

रैपिड रेल व मेट्रो के किनारे बसेंगे आधुनिक शहर

चर्चा में क्यों?

30 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने उन सभी शहरों में आधुनिक शहर बसाने का फैसला किया है, जो रैपिड रेल और मेट्रो रेल से जुड़े हैं। इनमें लखनऊ के अलावा कानपुर, आगरा, मेरठ और गाजियाबाद शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- इन शहरों में रैपिड रेल और मेट्रो के दोनों किनारे आधुनिक शहर बसाए जाएंगे। बड़े होटल, सभी सुविधायुत्त अपार्टमेंट, मल्टीलेवल पार्किंग, पार्क आदि की व्यवस्था होगी।
- सरकार की मंशा को देखते हुए आवास विभाग ने इन शहरों के विकास प्राधिकरणों को ज़ोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही सभी विकास प्राधिकरणों से इस संबंध में प्रस्ताव भी मांगा है।
- अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि आधुनिक शहर बसाने के उद्देश्य से ही उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) नीति-2022 जारी की गई है।
- इसका मकसद मेट्रो और रैपिड रेल वाले शहरों में कम ज़मीन पर अधिक निर्माण, आवासीय के साथ व्यावसायिक निर्माण और भू-उपयोग को बदलकर उस पर ज़रूरत के आधार पर निर्माण की सुविधा देना है।

नोट :